TIMES OF INDIA, Delhi, 12.8.2025
Page No. 13, Size:(8.98)cms X (12.65)cms.

SC seeks three rights panels' views on Talaq-e-Hasan plea

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: Supreme Court on Monday sought views of National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Women (NCW) and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on petitions by nine Muslim women challenging the validity of Talaq-e-Hasan, which enables a Muslim man to unilaterally divorce his wife by pronouncing talaq once a month for three consecutive months.

Eight years after a constitution bench struck down the practice of triple talaq (Talaq-e-Bidat) or instant divorce by a Muslim man by orally pronouncing 'talaq' thrice in one go, a bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi took up the petitions, six of them filed in 2022 and the rest in 2023, challenging the validity of Talaq-e-Hasan mode of divorce.

While allowing all intervention applications, the bench gave liberty to parties to file authoritative sources from books or scriptures to substantiate their pleas. "We feel that opinions of NHRC, NCW and NCPCR should be placed before the court for assistance in adjudicating these petitions," it said, requesting additional solicitor general K M Nataraj to bring on record the views of these national bodies.

When senior advocate M R Shamshad termed that these are Sharia law practices, being part of the religious law, and whose reforms should be left to the community and not be regulated by courts, advocate Ashwini Upadhyay said SC had in 2017 struck down triple talaq despite identical arguments advanced in support of it.

The bench asked Nataraj to place the views of the national bodies before the SC in four weeks and posted the matter for hearing on Nov 19.

DAINIK JAGRAN, Delhi, 12.8.2025
Page No. 12, Size:(5.34)cms X (10.74)cms.

'तलाक-ए-हसन' मामले में कोर्ट में अंतिम सुनवाई 19-20 नवंबर को

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को "तलाक-ए-हसन" और अन्य सभी प्रकार के "एकतरफा न्यायेतर तलाक" को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर की तारीख तय की। "तलाक-ए-हसन" मुसलमानों में तलाक का एक ऐसा रूप है जिसके तहत कोई पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार "तलाक" कहकर अपनी शादी तोड़ सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने पीड़ितों और अन्य असंतुष्ट पक्षों की याचिकाओं सहित विभिन्न याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से विचार मांगे। जब पीठ ने इस बाबत केंद्र के विचार जानने चाहे तो सरकार की ओर से पेश वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि केंद्र ने इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। लेकिन, ट्रिपल तलाक के मामले में अपने विचार दिए हैं जिनमें "एकतरफा न्यायेतर तलाक" के सभी रूपों का विरोध किया गया है। पीठ ने कहा, "यदि कोई सामग्री जैसे कि कुछ पुस्तकें या धर्मग्रंथ उपलब्ध हैं, तो उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। उचित सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राय रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए। हम अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज से अनुरोध करते हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी राय रिकार्ड में दर्ज की जाए।" गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें गाजियाबाद निवासी बेनजीर हिना द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। अपनी याचिका में उसने "तलाक-ए-हसन" से पीड़ित होने का दावा किया है।

- "एकतरफा न्यायेतर तलाक" को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अंतिम तारीख तय करते हुए विभिन्न आयोगों से मांगे विचार

AMAR UJALA, Delhi, 12.8.2025
Page No. 11, Size:(3.17)cms X (7.58)cms.

तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन पर मांगी राय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-किनाया, तलाक-ए-बाईन और अन्य सभी प्रकार के एकतरफा न्यायेतर तलाक पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से राय मांगी है। शीर्ष कोर्ट में इन प्रथाओं को असांविधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 19 व 20 नवंबर को होगी तलाक-ए-हसन एक ऐसी प्रथा है जिसमें तीन महीने तक हर माह एक बार तलाक कहा जाता है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन बार तलाक कहने को असांविधानिक करार दिया था।

मामला 3

- जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पीड़ितों और अन्य पीड़ित पक्षों की याचिकाओं पर तलाक की इन प्रथाओं से प्रभावित महिलाओं व विवाहेतर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर तलाक-ए-हसन के प्रभाव की जांच के लिए राय मांगी है। केंद्र की ओर से पेश वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने तीन तलाक मामले में विचार दिए हैं, जिसमें उन्होंने एकतरफा न्यायेतर तलाक के सभी रूपों का विरोध किया है। ब्यूरो

edrishti

`कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी -2025

https://www.edristi.in/hi/%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%AE/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B2-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95/

August 11, 2025

26 जुलाई, 2025 को 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया

इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के डॉ. राम मनोहर लोहिया पीठ के सहयोग से आयोजित किया गया था

यह पहल देश भर में पेशेवर वातावरण और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लेकर की गई।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण दिया

इस संगोष्ठी से प्राप्त कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और जागरूकता बढ़ाने के तीनों मोर्चों पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक ठोस और लक्षित प्रयास की आवश्यकता है।

महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत में अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में लक्षित जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर संवेदनशीलता की आवश्यकता है ताकि कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सके।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य महिलाओं के लिए समावेशी स्थानों का निर्माण सुनिश्चित करे, विशेष रूप से निर्णय लेने वाले निकायों में, ताकि संरचनात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

यह सिफारिश की जाती है कि शैक्षणिक संस्थान सक्रिय कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को विभिन्न लिंग-संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, साथ ही उन्हें विपरीत लिंग से जुड़ी स्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी जागरूक बनाया जाए।

लेखक- विवेक त्रिपाठी

Law Trend

`तलाक-ए-हसन' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19-20 नवंबर को करेगा अंतिम सुनवाई

https://lawtrend.in/sc-final-hearing-talaq-e-hasan-november-19-20/

By Law Trend | August 11, 2025 5:56 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'तलाक-ए-हसन' और अन्य सभी प्रकार के एकतरफा गैर-न्यायिक तलाक को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर 19-20 नवंबर को अंतिम सुनवाई की तारीख तय की।

तलाक-ए-हसन मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनाया जाने वाला तलाक का एक तरीका है, जिसमें पति हर महीने एक बार "तलाक" बोलता है और तीन महीने में तीसरी बार उच्चारण के बाद, यदि इस अवधि में पति-पत्नी का सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ हो, तो तलाक अंतिम हो जाता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से मामले पर अपनी राय देने को कहा है। अदालत ने सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि ये सुनवाई में मददगार साबित होंगी।

पीठ ने कहा, "यदि कोई सामग्री, जिसमें किताबें या धार्मिक ग्रंथ शामिल हों, उपलब्ध है तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी और एनसीपीसीआर की राय रिकॉर्ड पर होनी चाहिए।" अदालत ने एएसजी के. एम. नटराज से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी राय दाखिल हों।

केंद्र सरकार के रुख पर पूछे जाने पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन ट्रिपल तलाक केस में केंद्र ने सभी प्रकार के एकतरफा गैर-न्यायिक तलाक का विरोध किया था।

जब विरोधी पक्ष के वकील ने याचिकाओं की ग्राह्यता और याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाया, तो पीठ ने कहा, "हमें इस चरण पर तकनीकी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पीड़ित और प्रभावित पक्ष हमारे सामने हैं।"

अदालत नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें एक गाज़ियाबाद निवासी बेनज़ीर हीना की है, जिन्होंने खुद को तलाक-ए-हसन की पीड़िता बताया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र को लैंगिक और धर्म-निरपेक्ष, एक समान तलाक के आधार और प्रक्रिया बनाने का निर्देश देने की भी मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को इन याचिकाओं को मंजूर किया था और याचिकाकर्ताओं के पतियों को भी पक्षकार बनाकर उनसे जवाब मांगा था। अगस्त 2022 में अदालत ने कहा था कि उसका प्राथमिक ध्यान उन महिलाओं को राहत देने पर है, जो तलाक-ए-हसन की शिकार होने का दावा कर रही हैं, उसके बाद ही इस प्रथा की संवैधानिक वैधता पर फैसला होगा।

Jagran

`तलाक-ए-हसन' मामले में 19-20 नवंबर को होगी अंतिम सुनवाई, SC ने मांगे विचार; 'तलाक' बोलकर शादी तोड़ना होगा खत्म?

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन और अन्य एकतरफा न्यायेतर तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 19-20 नवंबर को निर्धारित की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग मानवाधिकार आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग से विचार मांगे हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है।

https://www.jagran.com/news/national-supreme-court-to-hear-pleas-against-talaq-e-hasan-in-november-24010202.html

By Agency Edited By: Prince Gourh Updated: Mon, 11 Aug 2025 07:04 PM (IST)

HighLights

SC 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

'तलाक-ए-हसन' में कोई पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार 'तलाक' कहकर शादी तोड़ सकता है

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'तलाक-ए-हसन' और अन्य सभी प्रकार के 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर की तारीख तय की।

'तलाक-ए-हसन' मुसलमानों में तलाक का एक ऐसा रूप है जिसके तहत कोई पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार 'तलाक' कहकर अपनी शादी तोड़ सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने पीड़ितों और अन्य असंतुष्ट पक्षों की याचिकाओं सहित विभिन्न याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से विचार मांगे।

केंद्र ने दायर नहीं किया जवाबी हलफनामा

जब पीठ ने इस बाबत केंद्र के विचार जानने चाहे तो सरकार की ओर से पेश वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि केंद्र ने इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। लेकिन, ट्रिपल तलाक के मामले में अपने विचार दिए हैं जिनमें 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' के सभी रूपों का विरोध किया गया है।

पीठ ने कहा, "यदि कोई सामग्री जैसे कि कुछ पुस्तकें या धर्मग्रंथ उपलब्ध हैं, तो उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। उचित सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राय रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए। हम अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज से अनुरोध करते हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी राय रिकार्ड में दर्ज की जाए।"

9 याचिकाओं पर हो रही सुनवई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें गाजियाबाद निवासी बेनजीर हिना द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। अपनी याचिका में उसने "तलाक-ए-हसन" से पीड़ित होने का दावा किया है।

Maktoob Media

Activists, civil groups slam ex-IPS officer's appointment as Haryana Police Complaints Authority chief

https://maktoobmedia.com/india/activists-civil-groups-slam-ex-ips-officers-appointment-as-haryana-police-complaints-authority-chief/

Maktoob Staff | August 11, 2025 | Modified : August 11, 2025

Activists and civil society groups criticised the appointment of a former IPS officer as chairperson of the Haryana Police Complaints Authority, citing the 2006 Supreme Court ruling that mandates such appointments follow its guiding principles.

The Haryana government appointed former IPS officer RC Mishra as Chairperson of the Authority and former IAS officer Lalit Siwach as a member on Friday, drawing sharp criticism from civil society groups.

According to the official appointment order issued by the office of Haryana Additional Chief Secretary (Home) Sumita Misra, "In pursuance of provisions contained in… Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), amended from time to time, read with Rule-3 of Haryana Police (Appointment of Chairperson and Members of Complaint Authorities) Rules, 2018 issued vide notification dated 07.12.2018, the Governor of Haryana is pleased to appoint the Chairperson and Members of the State Police Complaint Authority…"

The tenure of the Authority, as per the order, will be three years.

These groups argue that the Authority, tasked with hearing complaints against police officers, must be led by someone from a judicial background.

Citing the Supreme Court's ruling in Prakash Singh vs Union of India, they argued that the Police Complaints Authority should be headed by a retired High Court or Supreme Court judge.

In its Prakash Singh vs Union of India judgment, the Supreme Court directed that "there shall be a Police Complaints Authority at the district level to look into complaints against police officers up to the rank of Deputy Superintendent of Police," and "another Police Complaints Authority at the State level to look into complaints against officers of the rank of Superintendent of Police and above," with the district-level authority headed by a retired district judge and the state-level authority by a retired High Court or Supreme Court judge.

Meanwhile, Haryana government officials countered that the state's 2007 Police Act imposes no such restriction and permits the appointment of an IPS officer.

The Act empowers the Police Complaints Authority to inquire into allegations of serious misconduct against police personnel, either suo motu or based on complaints received from victims, their representatives, or the National or State Human Rights Commission, according to officials.

On Sunday, Punjab and Haryana High Court lawyer Hemant Kumar wrote to Governor Ashim Kumar Ghosh, urging the appointment of a retired High Court or Supreme Court judge as chairperson by the Supreme Court's 2006 directive.

They cited the 2015 Punjab and Haryana High Court decision that quashed the appointment of former IAS officer Pradeep Mehra as head of the Chandigarh Police Complaints Authority on similar grounds.

The State Police Complaint Authority is an independent entity constituted under the Haryana Police Act, 2007 to hear grievances of citizens against police officials.

As an oversight autonomous body, the Complaint Authority inquires into complaints of omission and commission on the part of police officers/officials, to bring accountability to the police and prevent abuse of powers.

CRUX

Dalit Christians in India protest denial of rights by government

https://cruxnow.com/church-in-asia/2025/08/dalit-christians-in-india-protest-denial-of-rights-by-government

By Nirmala Carvalho | Aug 11, 2025

MUMBAI, India – A black flag was hoisted at St Mary's Cathedral in Madurai, a city in the Indian state of Tamil Nadu, as part of a demonstration led by Antonysamy Savarimuthu and Anglican Bishop Jeyasingh Prince Prabhakaran.

This year, August 10 marked the 75th anniversary of the Scheduled Caste Presidential Order of August 10, 1950, which denied affirmative action to Dalit Christians.

The term "Dalit" refers to the "untouchables" under India's ancient caste system, meaning people considered unclean and therefore traditionally ostracized. Although caste distinctions were officially abolished by the Indian constitution in 1949, they remain strong in popular culture and the Dalits have traditionally been among India's most impoverished communities.

Addressing reporters, Savarimuthu said the demand was not for any special favor but for rightful entitlements.

"This is not a protest of Dalit Christians or Christians alone; it is not a minority protest. Every citizen must get their rights," he said. He noted that Dalit Sikhs and Buddhists were included in the Scheduled Caste list after protests, but Dalit Christians have been denied the same for 75 years on religious grounds.

August 10 is termed the "Black Day" by Dalit Christians and Muslims in India and marked by demonstrations from both communities.

"Though the Indian Constitution is highly revered by the people across the globe, the principles enshrined in that should be fully implemented," said Savarimuthu at the rally in Madurai.

Savarimuthu said August 10 of every year was observed as a black day for Dalit Christians as their demand to bring them under Scheduled Caste list was yet to be fulfilled.

"It is not just the protest staged by Christians, Muslims or minorities, but by those who believe in the Indian Constitution," the archbishop said, according to The Hindu.

"The demand has been on since the 1950s. What is our birth right – the status of SC/ST – cannot be taken away from us just because we have converted to Christianity," he said.

Archbishop Francis Kalist of Pondicherry and Cuddalore addressed the large gathering of the Black Day Protest at Cuddalore.

“Indian Christians will continue their protest until Dalit Christians are included in the SC list. Religious discrimination is against the Indian Constitution,” he said.

Father Z. Devasagaya Raj, who has served as the Executive Secretary of the CBCI Office for Scheduled Castes and Backward Classes, said demonstrations demanding the removal of this order have been organized in different parts of India.

“Many of the political parties support this demand,” he told Crux.

“Right wing parties are not in favor of including Dalit Christians in the Scheduled Caste list saying it will lead to the conversion of Dalit Hindus to Christianity. But it is not so. The argument is a wrong estimation of Dalits, suggesting that they would change their religion for little favors,” Raj said.

“The present government has appointed a commission under the retired Judge Konakuppakatil Gopinathan Balakrishnan. It bought more time to submit the report and prolonging the time to submit the report,” he explained.

Balakrishnan was the Chief Justice of the Supreme Court of India from 2007 to 2010, and later as served as chairperson of the National Human Rights Commission of India.

“We believe in the merit of the case and hope to get a positive judgement from the court,” Raj told Crux.

Deccan Herald

Dharmasthala mass burial: NHRC team visits site

SSP Yuvaraj, the team head, obtained from the Dharmasthala police station comprehensive details of unnatural death cases registered over the past decades.

https://www.deccanherald.com/india/karnataka/dharmasthala-mass-burial-nhrc-team-visits-site-3676232

Naina J A DHNS Last Updated : 11 August 2025, 22:41 IST

Mangaluru: While the Special Investigation Team (SIT) continues its probe into the mass burial case in Dharmasthala, a team from the National Human Rights Commission (NHRC) visited Dharmasthala village on Monday to gather information. The four-member NHRC team, led by Senior Superintendent of Police (SSP) Yuvaraj and DySP Ravi Singh, visited the SIT office in Belthangady, the Dharmasthala gram panchayat office, and the Dharmasthala police station, where they collected case-related details from officials. They are also said to have recorded a statement from the complainant witness in the case.

SSP Yuvaraj, the team head, obtained from the Dharmasthala police station comprehensive details of unnatural death cases registered over the past decades. A few NHRC officials visited the Dharmasthala gram panchayat office to gather information on unclaimed bodies buried in the village over the past decades. They collected details on the number of labourers engaged for body burial during this period and whether all of them were still alive. The officials also visited the homes of some labourers who had buried the bodies to record their statements. Additionally, a sanitation worker currently employed by the gram panchayat was summoned to the panchayat office for collecting further details. The NHRC team also inspected the site near the road to Bahubali Betta in Dharmasthala, where the SIT team had conducted an exhuming process on August 9.

Suo motu investigation

“We have not received any complaints about the case. On suo motu basis, we are examining and investigating," an NHRC official said. “We will check whether the gram panchayat and local police disposed of unidentified bodies as per procedure and whether there were any lapses. We will record statements from the complainant witness, his advocates, his supporters, and those opposing the investigation. We will also review the direction in which the SIT probe is progressing. We plan to stay here for about four days to collect information from all angles, and may stay longer if needed,” the official added.

SCC Times

NHRC takes suo motu cognizance of girl student burned by cook for asking for food at a residential school in Bihar

The NHRC has issued notices to the District Magistrate and the Superintendent of Police seeking a detailed report within 2 weeks.

https://www.scconline.com/blog/post/2025/08/11/nhrc-suo-motu-cognizance-girl-student-burned-by-cook-for-asking-for-food/

Published on August 11, 2025 By Editor

National Human Rights Commission: On 08-08-2025, the National Human Rights Commission ('NHRC') took suo motu cognizance of a media report concerning a girl student who was reportedly suffered injuries after being burned with a hot spatula by a cook at Kasturba Gandhi Girls Residential School in the Shakurabad area of Jehanabad, Bihar. The incident occurred after the student asked the cook for food. According to the media report, the same cook had been accused of a similar incident in the past and transferred to a different department due to a complaint against her.

The NHRC observed that if the contents of the report are true, raise a serious issue of human rights violation. Consequently, it issued notices to the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jehanabad, calling for a detailed report within 2 weeks.

The report is expected to include the health status of the injured student.

Deccan Chronicle

NHRC to Probe Secret Burial Claims in Dharmasthala

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/karnataka/nhrc-to-probe-secret-burial-claims-in-dharmasthala-1896961

DC Correspondent | 12 Aug 2025 2:07 AM IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has stepped in to probe allegations of mass secret burials in Dharmasthala, visiting places and meeting local officials.

A four-member NHRC team arrived in Belthangady taluk and began gathering records and information from various sources.

Mangaluru: The National Human Rights Commission (NHRC) has stepped in to probe allegations of mass secret burials in Dharmasthala, visiting places and meeting local officials.

A four-member NHRC team arrived in Belthangady taluk and began gathering records and information from various sources. The officials visited the Dharmasthala Gram Panchayat, the temple premises, the local police station, and the Special Investigation Team (SIT) office handling the ongoing probe.

According to sources the Commission has sought various documents from the Gram Panchayat and recorded statements from sanitation workers. The team also met several individuals privately to collect testimonies.

The NHRC's visit is expected to continue for the next four to five days.

According to sources the Commission has suo motu taken note of the development and has arrived in the temple town.

(Source : Deccan Chronicle)

Hindu

No funds for education dreams

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-funds-for-education-dreams/article69919891.ece

Published - August 12, 2025 01:29 am IST

Serish Nanisetti

Last week, a few dozen students of a Tribal Welfare Residential School for Girls in Parigi in Vikarabad in Telangana protested against the absence of math and chemistry faculty. In July, students of Left organisations agitated at the Secretariat in Hyderabad over poor education policies. Around the same time, the National Human Rights Commission (NHRC) directed the State government to investigate reports of over 800 children falling ill due to suspected food poisoning in Telangana's residential schools.

The protests by students and the directions of the NHRC cannot be seen in isolation. For the second year in a row, the Congress government in Telangana has let the education sector down. While the average allocation for education across States is around 15% of their total budget, according to a State Budget Analysis, Telangana allocates significantly less. For the year 2025-26, for instance, it earmarked only 7.9%.

The Congress rode to power in 2023 promising a higher outlay for education. Several education activists and NGOs helped the party during its campaign. On January 24, before the Budget was presented, activists demanded that the Congress raise the budgetary outlay for the sector, but this did not happen.

The education sector has been underfunded over the past decade in the State. At the time of Telangana's formation, the education budget of united Andhra Pradesh was 13.35% of budget estimates in 2013-14. After the formation of Telangana, this dropped to 10.89% in 2014-15 and further to 7.3% in 2022-23.

The number of personnel in the sector has also dropped. Telangana had 1,56,957 employees in the education sector at the time of its formation. By the time the Bharat Rashtra Samithi handed over the reins to the Congress, the number had declined to 1,51,801. In 2024-25, the number has gone up to 1,53,421, but this is still insufficient. The School Education Department had 1,37,252 employees in 2014-15; this dropped to 1,31,872 in 2022-23. How a reduction of 5,380 personnel has impacted the school education sector is anyone's guess. It is also pertinent to note that the government's reduced priority towards the sector comes at a time when schools have been struggling to get back on their feet after the pandemic.

A recent report shows how the system has been hollowed out due to the absence of regular teachers in rural and peri-urban areas, where the Congress performed well. Enrolment in government schools dropped from 70.1% in 2022 to 59.8% in 2024, according to the 2024 Annual Status of Education Report, published in January this year.

If the State had invested sufficient funds in the sector, students would have continued to go to government schools. The same report found that only 6.8% of students in Class 3 can read text prescribed for Class 2 students. This is a drop from 12.8% in 2018.

The government is not unaware of the needs of the education system. The Telangana Education Commission, set up in September 2024 under former IAS officer Akunukri Murali, had submitted a report on the state of education and the requirements to raise standards. It had called for an outlay of ₹5,000 crore for improving facilities in 100 mandals out of the 632 mandals in Telangana. The report had stated that a phase-wise outlay over six years would cover all the schools at a total cost of ₹31,600 crore. However, its suggestions remain on paper.

The earlier regime had focused on the marquee model of residential education where a few students are provided good quality education, food, and boarding. There are 3,170 residential schools catering to girls, minorities, Other Backward Classes, Scheduled Castes, and Scheduled Tribe students. The Congress government appears to be following a similar model by developing Young India Integrated Residential Schools. These schools will be able to cater only to a few as a vast majority of students in Telangana are day scholars whose parents prefer educational facilities in the neighbourhood. Unless there is more investment in government schools in every neighbourhood, the goal of universal primary education will be a mirage in Telangana.

In 1795, Surendranath Banerjee, one of the founding members of the Indian National Congress, spoke of how only 7.5% was spent by the British on education. He said this needed to change. More than 130 years later, spending a similar share on education does a great disservice to the young people of Telangana.

The Week

SC fixes Nov 19-20 for final hearing on pleas against `Talaq-e-Hasan'

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/08/11/lgd26-sc-talaq.html

PTI Updated: August 11, 2025 17:18 IST

New Delhi, Aug 11 (PTI) The Supreme Court on Monday fixed November 19-20 for the final hearing of pleas seeking declaration of "Talaq-e-Hasan" and all other forms of "unilateral extrajudicial divorce" as unconstitutional.

Talaq-e-Hasan is a form of divorce among Muslims through which a man can dissolve the marriage by pronouncing the word "talaq" once every month over a three-month period.

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi, while fixing the date for final hearing on a batch of pleas, including petitions by victims and other aggrieved parties, sought the views of National Commission for Women (NCW), National Human Rights Commission (NHRC) and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).

When the bench enquired about Centre's view, its counsel Ashwini Kumar Upadhyay said it had not file any counter affidavit in the matter as such but given views in Triple Talaq case in which they have opposed all forms of "unilateral extrajudicial divorce".

The top court allowed all the intervention applications and said they could assist the court in the hearing.

"If there is any material including some books or scriptures that may be produced. An opinion of the NCW, NHRC and NCPCR should be on record for proper assistance. We request ASG K M Nataraj to seek instructions and ensure that their opinions are brought on record," the bench said.

When one of the counsel appearing for opposing parties said there could be issues of maintainability and locus of petitioners challenging the Talaq-e-Hasan, the bench said the victims and aggrieved parties were before it and there couldn't be an issue over locus standi and maintainability as a result.

"We should not be worried about technicalities at this stage. There are individuals who are affected and are before this court. We will look into it," the bench said, adjourning the matter.

The apex court was hearing nine petitions, including the one filed by Ghaziabad resident Benazeer Heena, claiming to be aggrieved by Talaq-e-Hasan.

They have also sought a direction to the Centre to frame the guidelines for gender and religion-neutral and uniform grounds of divorce and procedure for all citizens.

The top court had previously impleaded husbands of the petitioners and sought their replies on the pleas.

On October 11, 2022, the top court admitted the pleas challenging the practice and all other forms of unilateral extrajudicial divorce and sought directions to declare them unconstitutional.

The top court in August, 2022 said its primary focus was to provide relief to women, who claimed to be victims of Talaq-e-Hasan, before deciding the constitutional validity of this form of divorce.

Under Talaq-e-Hasan, a divorce gets formalised after the third utterance of the word talaq in the third month if cohabitation has not resumed during this period.

However, if cohabitation resumes after the first or second utterance of talaq, the parties are assumed to have reconciled.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

TIMES OF INDIA, Delhi, 12.8.2025
Page No. 13, Size:(8.98)cms X (12.65)cms.

SC seeks three rights panels' views on Talaq-e-Hasan plea

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: Supreme Court on Monday sought views of National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Women (NCW) and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on petitions by nine Muslim women challenging the validity of Talaq-e-Hasan, which enables a Muslim man to unilaterally divorce his wife by pronouncing talaq once a month for three consecutive months.

Eight years after a constitution bench struck down the practice of triple talaq (Talaq-e-Bidat) or instant divorce by a Muslim man by orally pronouncing 'talaq' thrice in one go, a bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi took up the petitions, six of them filed in 2022 and the rest in 2023, challenging the validity of Talaq-e-Hasan mode of divorce.

While allowing all intervention applications, the bench gave liberty to parties to file authoritative sources from books or scriptures to substantiate their pleas. "We feel that opinions of NHRC, NCW and NCPCR should be placed before the court for assistance in adjudicating these petitions," it said, requesting additional solicitor general K M Nataraj to bring on record the views of these national bodies.

When senior advocate M R Shamshad termed that these are Sharia law practices, being part of the religious law, and whose reforms should be left to the community and not be regulated by courts, advocate Ashwini Upadhyay said SC had in 2017 struck down triple talaq despite identical arguments advanced in support of it.

The bench asked Nataraj to place the views of the national bodies before the SC in four weeks and posted the matter for hearing on Nov 19.

Law Trend

SC to Hold Final Hearing on November 19-20 in Pleas Challenging `Talaq-e-Hasan'

https://lawtrend.in/sc-to-hold-final-hearing-on-november-19-20-in-pleas-challenging-talaq-e-hasan/

By Law Trend | August 11, 2025 5:54 PM

The Supreme Court on Monday fixed November 19–20 for the final hearing of a batch of petitions seeking to declare Talaq-e-Hasan and other forms of unilateral extrajudicial divorce as unconstitutional.

Talaq-e-Hasan is a form of divorce in which a Muslim man can dissolve a marriage by pronouncing the word "talaq" once a month over three months, with the divorce becoming final upon the third pronouncement if cohabitation has not resumed.

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi directed that the National Commission for Women (NCW), National Human Rights Commission (NHRC), and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) submit their opinions in the matter. The court also allowed all intervention applications, noting that they could assist during the hearing.

"If there is any material, including books or scriptures, that may be produced. An opinion of the NCW, NHRC, and NCPCR should be on record for proper assistance," the bench observed, asking ASG K M Nataraj to ensure these are filed.

When asked about the Centre's stand, counsel Ashwini Kumar Upadhyay said no counter-affidavit had been filed in this case but pointed out that in the Triple Talaq matter, the government had opposed all forms of unilateral extrajudicial divorce.

Rejecting objections on maintainability and locus standi, the bench said, "We should not be worried about technicalities at this stage. There are individuals who are affected and are before this court."

The court is hearing nine petitions, including one filed by Ghaziabad resident Benazeer Heena, who claims to be a victim of Talaq-e-Hasan. The petitioners have also sought directions to the Centre to frame gender- and religion-neutral uniform grounds and procedures for divorce applicable to all citizens.

The Supreme Court had admitted the pleas on October 11, 2022 and previously impleaded the petitioners' husbands, seeking their replies. In August 2022, the bench had noted that its primary focus was to grant immediate relief to women claiming to be victims before examining the constitutional validity of the practice.

LawChakra

Supreme Court Seeks NCW, NHRC, NCPCR Views on Petitions Against Talaq-e-Hasan

https://lawchakra.in/supreme-court/ncw-nhrc-ncpcr-views-on-talaq-e-hasan/?amp=1

Hardik Khandelwal | 2 hours ago

The Supreme Court has called for opinions from NCW, NHRC, and NCPCR while hearing pleas challenging the validity of Talaq-e-Hasan. The case, filed by journalist Benazeer Heena, will be heard finally on November 19, 2025.

New Delhi: On August 11, the Supreme Court asked for the opinions of the National Commission for Women (NCW), the National Human Rights Commission (NHRC), and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) while hearing petitions that challenge the practice of Talaq-e-Hasan.

The matter was heard by a Bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi.

During the hearing, Advocate Ashwini Kumar Upadhyay informed the Court that most of the points in this case had already been discussed earlier in the triple talaq case. However, the Bench remarked,

“We’ll hear the matter individually.”

In its order, the Supreme Court stated,

“We allow all the IAs seeking intervention. They may not file counter affidavits but assist us during final hearing. If there is any material including some books or scriptures, that may be produced. An opinion of the NCW, NHRC, and NCPCR should be on record for proper assistance. We request Shri K.M. Nataraj, ASG, to seek instructions and ensure that their opinions are brought on record.”

When one of the Respondents highlighted that in the Shayara Bano case, the majority judges had held Talaq-e-Biddat to be arbitrary but had not made rules regulating Sharia, Justice Surya Kant responded,

“We should not be worried about technicalities at this stage. There are individuals who are affected and are before this Court. We will look into it.”

The Court has now fixed the case for final hearing on November 19, 2025.

Background of the case

The petition was filed by Benazeer, a journalist, after her husband sent her the first notice of Talaq-e-Hasan through a lawyer. She also requested the Court to direct the Central Government to make guidelines for neutral and uniform grounds and procedures for divorce that would apply to all citizens, regardless of religion.

In April 2022, an FIR was filed at Vijay Nagar Police Station, Ghaziabad, against Benazeer Heena's husband and his relatives under Sections 498A, 332, 504, 506, and 406 of the Indian Penal Code (IPC) and the Dowry Prohibition Act.

In her petition, she asked the Court to declare Talaq-e-Hasan and all other types of "unilateral extra-judicial talaq" as invalid and unconstitutional, saying they were arbitrary, irrational, and violated the fundamental rights of women.

Talaq-e-Hasan is a type of divorce in which the husband pronounces the word "talaq" once a month, over a period of three months. If the couple does not start living together again during this period, the divorce becomes final after the third pronouncement in the third month.

However, if the couple reconciles and resumes living together after the first or second pronouncement, the divorce process stops and those earlier pronouncements become invalid.

On May 25, 2022, Senior Advocate Pinky Anand mentioned the petition before a Bench of Justice D.Y. Chandrachud and Justice Bela Trivedi, saying that Benazeer had already received the second talaq notice. At that time, the Bench said there was no urgency in the matter but allowed her to bring it up again the following week.

Later, on August 16, 2022, a Bench of Justice S.K. Kaul and Justice M.M. Sundresh gave time to Pinky Anand to discuss with Benazeer whether she would agree to divorce by mutual consent if the meher (dower) was taken care of.

The Bench observed,

"Prima facie this is not improper. Women also have an option of Khula. Prima facie I do not agree with the petitioners. I don't want to make an agenda of it for any other reason."

Case Title:

Benazeer Heena v. Union of India & Ors.

Times of India

Supreme Court seeks three rights panels' views on Talaq-e-Hasan plea

https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-seeks-three-rights-panels-views-on-talaq-e-hasan-plea/articleshow/123246108.cms

TNN | Aug 12, 2025, 04.56 AM IST

NEW DELHI: Supreme Court on Monday sought views of National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Women (NCW) and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on petitions by nine Muslim women challenging the validity of Talaq-e-Hasan, which enables a Muslim man to unilaterally divorce his wife by pronouncing talaq once a month for three consecutive months.

Eight years after a constitution bench struck down the practice of triple talaq (Talaq-e-Bidat) or instant divorce by a Muslim man by orally pronouncing 'talaq' thrice in one go, a bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi took up the petitions, six of them filed in 2022 and the rest in 2023, challenging the validity of Talaq-e-Hasan mode of divorce.

While allowing all intervention applications, the bench gave liberty to parties to file authoritative sources from books or scriptures to substantiate their pleas. "We feel that opinions of NHRC, NCW and NCPCR should be placed before the court for assistance in adjudicating these petitions," it said, requesting additional solicitor general K M Nataraj to bring on record the views of these national bodies.

When senior advocate M R Shamshad termed that these are Sharia law practices, being part of the religious law, and whose reforms should be left to the community and not be regulated by courts, advocate Ashwini Upadhyay said SC had in 2017 struck down triple talaq despite identical arguments advanced in support of it.

The bench asked Nataraj to place the views of the national bodies before the SC in four weeks and posted the matter for hearing on November 19.

Navbharat

उच्चतम न्यायालय ने तलाक-ए-हसन के खिलाफ याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की

https://navabharat.news/supreme-court-fixes-date-for-final-hearing-on-petitions-against-talaq-e-hasan/

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तलाक-ए-हसन और अन्य सभी प्रकार के 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' को असंवैधानिक घोषित करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर की तारीख तय की. तलाक-ए-हसन मुसलमानों में तलाक का एक रूप है, जिसके माध्यम से एक पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक शब्द कहकर विवाह को समाप्त कर सकता है.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पीड़ितों और अन्य पक्षों की याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से विचार मांगे.

जब पीठ ने केंद्र की राय के बारे में पूछा, तो उसके वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, लेकिन फौरी तीन तलाक मामले में विचार दिए हैं, जिसमें उन्होंने "एकतरफा न्यायेतर तलाक" के सभी रूपों का विरोध किया. शीर्ष अदालत ने सभी हस्तक्षेप अर्जियों को मंजूर कर लिया और कहा कि वे सुनवाई में अदालत की सहायता कर सकते हैं.

पीठ ने कहा, "पुस्तकें या धर्मग्रंथ समेत यदि कोई सामग्री है, तो उसे पेश किया जा सकता है. उचित सहायता के लिए एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी और एनसीपीसीआर की राय रिकॉर्ड में होनी चाहिए. हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से आग्रह करते हैं कि वे निर्देश प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि उनकी राय रिकॉर्ड में लाई जाए." उच्चतम न्यायालय नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इनमें गाजियाबाद निवासी बेनजीर हीना द्वारा दायर याचिका भी शामिल है, जिसमें दावा किया गया कि वह तलाक-ए-हसन से पीड़ित हैं.

उन्होंने केंद्र को सभी नागरिकों के लिए लिंग और धर्म के प्रति तटस्थ तथा तलाक के समान आधार और प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ताओं के पतियों को भी पक्षकार बनाया था और उनसे याचिकाओं पर जवाब मांगा था. शीर्ष अदालत ने 11 अक्टूबर, 2022 को इस प्रथा और एकतरफा न्यायेतर तलाक के अन्य सभी रूपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया.

तलाक-ए-हसन के तहत, तीसरे महीने में तलाक शब्द के तीसरी बार उच्चारण के बाद तलाक औपचारिक रूप से संपन्न हो जाता है, यदि इस अवधि के दौरान सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ हो. हालांकि, यदि पहली या दूसरी बार तलाक कहने के बाद साथ रहना पुन? शुरू हो जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है.

Daink Bhaskar Hindi

राजनीति: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन पर मांगी राय, अब नवंबर में होगी सुनवाई

https://www.bhaskarhindi.com/other/supreme-court-1171789

11 Aug 2025 5:17 PM

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बाईन जैसी प्रथाओं पर गहन जांच शुरू की है। कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से राय मांगी है। यह कदम तलाक पीड़िता बेनजीर हिना की याचिका के बाद उठाया गया है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बाईन जैसी प्रथाओं पर गहन जांच शुरू की है। कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से राय मांगी है। यह कदम तलाक पीड़िता बेनजीर हिना की याचिका के बाद उठाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक (तलाक-ए-बिदत) को 2017 में असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद, तलाक-ए-हसन जैसी प्रथाएं अब भी जारी हैं। तलाक-ए-हसन में तीन महीने के अंदर हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है, जिससे रिश्ता खत्म हो जाता है। इससे महिलाओं और उनके बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने इन प्रथाओं के सामाजिक और कानूनी प्रभावों की जांच के लिए आयोगों को नोटिस जारी किया है।

सोमवार (11 अगस्त) की सुनवाई में अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन जनहित याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि ये याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। बोर्ड का तर्क है कि ये मुद्दे निजी कानून के दायरे में आते हैं। वहीं, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि तीन तलाक मामले में कोर्ट ने तलाक-ए-हसन जैसे अन्य तरीकों पर फैसला नहीं दिया था। लेकिन, अब इसकी जरूरत है। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि एकतरफा तलाक, चाहे वह चिट्ठी, ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस से हो, बंद होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 और 20 नवंबर 2025 को होगी। उपाध्याय ने कहा, " इस फैसले से देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा और तलाक की प्रक्रिया हर किसी के लिए समान होगी। गुजारा भत्ता भी सभी को समान रूप से मिलना चाहिए और एक समान कानून लागू होना चाहिए, जो एकतरफा तलाक पर रोक लगाए।"

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष

/ वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Bharat Express

सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में प्रचलित तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-किनाया पर NHRC, NCW और NCPCR से मांगी राय

कोर्ट ने प्रभावित महिलाओं और विवाहेत्तर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर तलाक -ए-हसन के प्रभाव की जांच करने के लिए राय मांगी है. कोर्ट नवंबर को तीसरे हफ्ते में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

https://bharatexpress.com/legal/supreme-court-seeks-opinion-from-nhrc-ncw-and-ncpcr-on-talaq-e-hasan-talaq-e-ahsan-and-talaq-e-kinaya-prevalent-among-muslims-549934

गोपाल कृष्ण August 11, 2025 6:52 pm

Edited by Md Shadan Ayaz

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुसलमानों में प्रचलित तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-किनाया, पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से राय मांगी है.

कोर्ट ने प्रभावित महिलाओं और विवाहेत्तर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर तलाक -ए-हसन के प्रभाव की जांच करने के लिए राय मांगी है. कोर्ट नवंबर को तीसरे हफ्ते में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका तलाक पीड़िता बेनजीर हिना सहित आठ लोगों की ओर से दायर की गई है.

दायर याचिकाओं में कहा गया है कि तलाक-ए-हसन जैसी व्यवस्था पुरुषों को अपनी मर्जी से शादी खत्म करने का एकतरफा अधिकार देती है. यह मुस्लिम महिलाओं को असमानता की स्थिति में रखता है. इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव न होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है.

तलाक-ए-हसन इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी को तीन महीने में तीन बार तलाक बोलकर तलाक देता है. इससे महिलाओं और उनके बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है.

कोर्ट ने इन प्रथाओं के एक सामाजिक और कानूनी प्रभावों की जांच के लिए महिला आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर राय मांगा है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कई इस्लामी राष्ट्रों ने इस तरह की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि यह सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से याचिकाकर्ता की तरह मुस्लिम महिलाओं को परेशान करना जारी रखे हुए हैं.